हल्द्वानी (नैनीताल) एवं देहरादून से एक साथ प्रकाशित

समाचारों को विस्तार से व तत्काल पढ़ने के लिए क्लिक करें
Web:- www.jokhimnews.com
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में "ए" श्रेणी में सूचीबद्ध

जोखिम

भय भूख एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत् निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 318 | देहरादून बुधवार 11 फरवरी 2026 | मूल्य :रू 2 | पृष्ठ : 8

सीएम धामी ने किया मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ

-मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

-राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को मिलेगी नई दिशा

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर (42 लाभार्थी) , देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी (23) एवं उधमसिंहनगर (87) के कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा दी जा रही है। महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति संभव नहीं है। महिला के सशक्त होने से परिवार के साथ पूरा समाज सशक्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि दी जा रही है। शेष 7 जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़, महीने के अंत तक डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा इस योजना में हमने विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन का भार उठाने वाली महिलाओं के साथ एसिड अटैक, आपराधिक घटना की पीड़िता, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना के शुरू होने से राज्य की नारी शक्ति अब नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं । महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना के साथ ही ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, राज्य की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान किए जा रहें हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएँ 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएँ सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। प्रदेश की 1 लाख 68 हजार से अधिक बहनों ने लखपति दीदी' बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने का काम किया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।

कैंट क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हो समाधान

देहरादून संवाददाता. भाजपा महानगर संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ महेश पांडे ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से दिल्ली स्थित सरकारी आवास में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैंट के चुनाव नहीं होने के मुद्दे और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पूर्व सीएम को अवगत करवाया कि करीब चार साल पहले पूर्व छावनी परिषद क्लेमेनटाउन और अन्य कैंट को भी लोकल बॉडी में विलय का गजट नोटिफिकेशन किया गया था। उसके बाद से लगातार राज्य सरकार शहरी विकास विभाग और कैंट बोर्ड अधिकारियों की विलय को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ।

टेंट हाउस में आग से मचा हड़कंप, 30 हजार लीटर पानी की बौछार से बुझाई गई लपटें

देहरादून संवाददाता. क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में मंगलवार आधी रात एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि इसकी ऊंची लपटें आसपास के रिहायशी मकानों तक पहुंची। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और करीब 30 हजार लीटर पानी की मदद से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रताप मार्ग स्थित नरेन्द्र टेंट हाउस (मालिक नरेन्द्र कुमार) के खाली प्लॉट में टेंट और शामियाने का भारी मात्रा में सामान रखा हुआ था। अचानक वहां आग सुलग उठी। सिटी कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुई। फायर स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक टेंट हाउस में लकड़ी की फोल्डिंग टेबल, बर्तन, भट्टियां, मेट और रजाई-गद्दे भारी मात्रा में रखे थे। इन ज्वलनशील सामानों के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें बगल के मकानों की तरफ बढ़ने लगीं, जिससे घरों में सो रहे लोग दहशत में बाहर निकल आए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि देर रात जैसे ही आग की सूचना मिली, हमारी यूनिट तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। आग टेंट के सामान में होने के कारण तेजी से फैली थी। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के घरों तक पहुँचने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छह गाड़ियों और रिले पंपिंग का सहारा आग की भयावहता को देखते हुए अन्य फायर स्टेशनों से भी अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने रिले पंपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। एक डिलीवरी होज पाइप और दो होजरील के जरिए आग को चारों तरफ से घेरा गया। काफी संघर्ष के बाद आग को रिहायशी इलाके में फैलने से रोका गया।

संक्षिप्त समाचार...

नगर निगम के वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या में अंतर से पार्षद नाराज

देहरादून संवाददाता. नगर निगम के पार्षदों ने वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पार्षद अभिषेक पंत ने बताया कि निगम के वार्डों में कर्मचारियों की संख्या में बड़ा अंतर है। इसका सफाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। पार्षद कपिल धर और संजीत बंसल ने कहा कि निगम को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

उत्तराखंड से छीनी गई रणजी सेमीफाइनल की मेजबानी

देहरादून संवाददाता.रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच की मेजबानी उत्तराखंड से छीन ली गई है। बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर राकेश कुमार द्वारा देहरादून के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निरीक्षण में पिच व मैदान की हालत खराब पाई गई, जिसके बाद मैच को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। अब मुकाबला इकाना स्टेडियम, लखनऊ या ग्रीन पार्क, कानपुर में कराया जाएगा। मेजबानी छिनने से खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसले पर खेद जताते हुए स्टेडियम को शीघ्र अपग्रेड करने की बात कही है।

नेहरु कॉलोनी और पटेलनगर से दिनदहाड़े दो दुपहिया चोरी

देहरादून संवाददाता. दून में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दिनदहाड़े दो दुपहिया वाहन चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सम्पादकीय

अमल की ताक में अदालत के महत्त्वपूर्ण आदेश

आरटीई कानून लागू हुए 16 वर्ष गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से जाहिर है कि सरकारों ने उस धारा के तहत अपने दायित्व को नहीं निभाया। यानी लड़कियों के लिए अलग शौचालय की जरूरत पूरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या का ऊंचा सैद्धांतिक महत्त्व है कि मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को इससे संबंधित सुविधाएं मिलें, यह सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इस सिलसिले में लड़के, लड़कियों, और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालय बनाने तथा लड़कियों को सेनेटरी पैड मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट की ये राय सटीक है कि मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के सुरक्षित, प्रभावी, और किफायती उपाय उपलब्ध ना होने पर लड़कियों की गरिमा प्रभावित होती है। इसलिए अदालत ने इन सुविधाओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं का मौलिक अधिकार बना दिया है। यानी न्यायालय ने जीवन के अधिकार संबंधी अनुच्छेद का विस्तार किया है। ठीक ऐसा ही विस्तार एक दशक पहले कोर्ट की एक संविधान पीठ ने किया था, जब निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। दरअसल, गुजरे दशकों में कोर्ट ने अपने कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों एवं व्याख्याओं के जरिए नागरिक समाज के विभिन्न समूहों के मौलिक अधिकारों का विस्तार किया है। लेकिन बात घूम-फिर कर अमल पर आ जाती है। पूर्व निर्णय से निजता कितनी सुरक्षित हुई? खुद संसद ने जीवन के बुनियादी हक संबंधी अनुच्छेद 21 में उपधारा 21-ए जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार बनाया था। उसके तहत स्कूल को खास ढंग से परिभाषित किया गया, जिसमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की अनिवार्यता उपलब्धता शामिल है। यह कानून लागू हुए 16 वर्ष गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से जाहिर है कि सरकारों ने उस धारा के तहत अपने दायित्व को नहीं निभाया। यानी ये जरूरत पूरी नहीं की गई। तो नए आदेश पर पालन सुनिश्चित कौन कराएगा? इसका उल्लंघन होने पर जवाबदेही कैसे तय होगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक संवैधानिक प्रावधान, कानून, और सर्वोच्च अदालत के महत्त्वपूर्ण आदेश आज भी अमल की ताक में हैं।

विकसित भारत 2047 की ओर स्मार्ट रास्ता हड़ताल नहीं, बल्कि श्रम संहिता

डॉ. दीपक जायसवाल

पीढ़ियों से, भारत के श्रमिकों ने एक पुरानी और टुकड़ों में बंटी श्रम प्रणाली का बोझ उठाया है, जो अक्सर उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। असंगठित, संविदा और उभरते गिग क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक नीति-परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं। चार श्रम संहिताएँ इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग तीन दर्जन अलग-अलग कानूनों को एक सुसंगत, एकल ढांचे में लाकर, ये संहिताएँ न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है।एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू), कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी को श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समय में श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम हित में है।श्रम संहिताएं कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं। ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम हैं। 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अस्पष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके।श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है, जो वे श्रमिकों को प्रदान करने का प्रयास करती हैं। वेतन संहिता सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार, असंगठित, संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है। इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं।औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेज विवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है। कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शायद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं। संवाद, नियम-आधारित सुधार और मुद्दा-विशेष पर चर्चा के जरिये श्रमिकों के हित बेहतर तरीके से पूरे किये जा सकते हैं, बजाय इसके कि आपस में टकराव हो, जिससे पारिश्रमिक हानि, उत्पादन में रुकावट और रोजगार असुरक्षा का जोखिम पैदा होता है।विशेष रूप से श्रम बल के सबसे कमजोर वर्गों के लिए।यह दावा करना भी गलत है कि श्रम संहिताएँ बिना परामर्श के लागू की गई हैं। सुधार प्रक्रिया में त्रिपक्षीय चर्चाओं के कई दौर, संसद की स्थायी समितियों में विचार-विमर्श और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद शामिल थे। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बातचीत और संस्थागत संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि उन व्यवधानों के द्वारा जो अंततः स्वयं श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचाते हैं।जब भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूपांतरण के दौर से गुजर रही है और राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, श्रमिक संघों को विघटन के बजाय जिम्मेदार कार्रवाई का चयन करना चाहिए।

औशंकराचार्य वाला विवाद खड़ा

हरिशंकर व्यास

सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि साजिश के तहत यूजीसी के नियम जारी किए गए। औशंकराचार्य वाला विवाद खड़ा किया गया। कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने और उनके सबसे निष्ठावान वोट को उनसे अलग करने के लिए किसी ने अंदर से साजिश की और यूजीसी का नियम जारी हुआ। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा हो गया इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने का विरोध नहीं किया। सवाल है कि जिस पार्टी में नेता, मंत्री, अधिकारी सब ऊपर के आदेश से ही सांस लेते हैं वहां किसने ऐसा करने की साजिश की? भाजपा इकोसिस्टम के लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बना रहे हैं। वे पिछड़ी जाति से आते हैं और खुल कर पिछड़ा राजनीति करने में यकीन करते हैं। कहा जा रहा है कि ओडिशा का मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद जब भाजपा का अध्यक्ष पद भी हाथ से निकला तो संसदीय समिति की सिफारिशों में अदलाबदली करके प्रधान ने ऐसा नियम जारी करवा दिया, जिससे पार्टी फंसी। शंकराचार्य वाले मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ के विवाद और साजिश के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पर सब कुछ हुआ है।यूजीसी नियमों में साजिश का दूसरा पहलू दिल्ली बनाम लखनऊ के विवाद के तौर पर पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जान बूझकर अगड़ा बनाम पिछड़ा का मुद्दा बनाया गया और अगड़ों के विरोध को खूब फैलाया गया। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में बाकी किसी भी राज्य के मुकाबले अगड़ी जातियां खास कर ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार सबसे ज्यादा हैं। अगर वे भाजपा से नाराज होते हैं तो अगले साल के चुनाव में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इसका उलटा हो गया तो क्या होगा? अगर अगड़े नाराज हुए और सचमुच पिछड़े भाजपा के पक्ष में गोलबंद हो गए तब तो यह दांव मास्टरस्ट्रोक बन जाएगा?हालांकि साजिश थ्योरी वाले इसे नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि 18 फीसदी मुस्लिम और 10 फीसदी यादव तो पूरी तरह से सपा के साथ हैं। 20 फीसदी दलितों में से हर हाल में 10 फीसदी दलित मायावती का साथ देंगे। अगर 20 से 22 फीसदी सवर्ण भाजपा से छिटके तो भाजपा बुरी तरह से हारेगी। तभी साजिश थ्योरी वाले इसे योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं।इसी तरह, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पिछले दिनों देश के एक बडे उद्योगपति के यहां जाने की तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के प्रति सद्भाव दिखाया और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। इस पर कहा जा रहा है कि वे दिल्ली के नेता के करीबी हैं। इसलिए उन्होंने अलग लाइन पकड़ी। अब सवाल है कि अगर कोई साजिश थी तो योगी आदित्यनाथ को किसने रोका था कि वे अपने प्रशासन के लोगों को शंकराचार्य के पास भेजें और मामला खत्म कराए? उनको मनाने का जो काम शंकराचार्य के माघ मेला छोड़ने के बाद किया गया वह पहले भी हो सकता था। जो हो इन दोनों घटनाओं ने देश की राजनीति में नए सिरे से ध्रुवीकरण की संभावना को जन्म दिया है। तभी यह भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यथास्थिति को तोड़ते रहते हैं ताकि समाज और राजनीति में उथलपुथल मचा कर अपनी लोकप्रियता कायम रखे।

पूर्व विधायक चौंपियन के फार्म से पॉपुलर के पौधे उखाड़े

रुड़की कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने खानपुर के पूर्व विधायक के फार्म से हजारों पौधे उखाड़कर फेंक दिए गए। वहीं, एक रिटायर्ड कर्नल के बाग से लाखों के आम के पेड़ काटकर चोरी कर लिए गए। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौंपियन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लंढौरा स्थित उनकी पैतृक भूमि पर दो सप्ताह पहले 2000 पॉपुलर के पौधे लगाए गए थे। शनिवार रात अराजक तत्वों ने पौधों को उखाड़कर नुकसान पहुंचाया। पूर्व विधायक ने मोहल्ला बाहरी किला निवासी तीन सगे भाइयों नफीस, फारुख और मन्नी पर संदेह जताते हुए तहरीर दी है। दूसरा मामला ग्राम गदरजुड्डा का है। वहां देहरादून निवासी सेना के रिटायर्ड कर्नल संजीव सिंह के खेत से चोरों ने 60 साल पुराने नौ आम के पेड़ काटकर चोरी कर लिए। कर्नल संजीव सिंह ने बताया कि उक्त भूमि पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। रविवार रात करीब 11:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि चोरों ने हरे-भरे पेड़ों को काटकर लकड़ी गायब कर दी है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

बीस सूत्री कार्यक्रमों पर आंध्र-उत्तराखंड ने बांटे अनुभव

-आंध्र की बीस सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष ने कहा-हम भी इन पर विचार करेंगे

देहरादून संवाददाता. उत्तराखंड में बीस सूत्री कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिस तरह से विभाग कार्य कर रहे हैं, उसने आंध्र प्रदेश को काफी प्रभावित किया है। आंध्र की बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष दिनकर लंका का कहना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उत्तराखंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेज अपना रहा है, वे बहुत अच्छी है। इन्हें आंध्र प्रदेश में अपनाने के संबंध में विचार किया जाएगा।मंगलवार को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के बीस सूत्री कार्यक्रमों के संबंध में अनुभवों को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड ने बीस सूत्री कार्यक्रमों के कियान्वयन के लिए अपनाई जा रही पद्धति को विस्तार से सामने रखा। सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।एसडीजी में जमा चुका है उत्तराखंड सिक्का: सेतु आयोग के निदेशक डा.मनोज कुमार पंत ने प्रस्तुतिकरण देते हुए अवगत कराया कि वर्ष 2016-17 से राज्य मे लगातार 369 संकेतांकों के माध्यम से एसडीजी का अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में

एसडीजी के 39 संकेतांकों के आधार पर ही मासिक रैंकिंग जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में राज्य अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के मिशन के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड 2047 की रूपरेखा तैयार की गई है। इस क्रम में विभागों के स्तर पर अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए है। राज्य में संचालित की जा रही योजनाओं के बजट को भी उसी के अनुरूप वित्त पोषित किया जा रहा है।बीस सूत्री कार्यक्रमों की राज्य में पैनी निगरानी : कार्यक्रम में बीस सूत्री कार्यक्रम के संयुक्त निदेशक त्रिलोक सिंह अन्ना ने जानकारी दी कि बीस सूत्री कार्यक्रम की अनुश्रवण प्रणाली को सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्तमान में इसके तहत् 81 योजनाओं के 246 सूचकों की प्रगति के संबंध में रिपोर्टिंग की जा रही है, जिसमें से 45 सूचकों के आधार पर नियमित जनपदवार मासिक रैंकिंग जारी की जाती है। राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर की समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। टास्क फोर्स अधिकारी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन करते हैं। रिपोर्टिंग प्रक्रिया को पेपरलैस बनाने के उद्देश्य से डाटा संचरण की प्रणाली को आनलाइन किया गया है।जनपदों में स्वस्थ प्रतिस्पधर्ा, पुरस्कार से प्रोत्साहन: कार्यक्रम में बीस सूत्री कार्यक्रम उत्तराखंड के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कार्यक्रमों की अनुश्रवण प्रणाली को विकासखण्ड स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया है। ताकि जनपदों में स्थित विकासखण्डों की प्रगति संबंधी स्थिति को बेहतर रूप में आंकलित किया जा सके। साथ ही जनपदों के मध्य स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त प्रथम तीन श्रेणी प्राप्त जनपदों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। विकासखण्ड स्तरीय फ्रेमवर्क के तहत 56 रैंकिंग तथा 49 नॉन रैंकिंग सूचकों के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है। दिनकर ने आंध्र प्रदेश की स्थिति को रखा सामने: कार्यक्रम में बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष दिनकर लंका ने अवगत कराया कि आंध्र प्रदेश राज्य में भी विकसित भारत-2047 की तर्ज पर स्वर्ण आंध्र-2047 मिशन पर कार्य किया जा रहा है। उन्हों ंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को संसदीय क्षेत्र, जनपद, विकासखण्ड से लेकर ग्राम स्तर तक आच्छादित करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य बेहतरीन कार्य कर रहा है।विभागों ं ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताए प्रयास: राज्य में संचालित विभिन्न केंद्र पोषित तथा राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में जानकारी भी कार्यक्रम में रखी गई। समग्र शिक्षा विभाग के स्तर पर राज्य में किए जा रहे नवाचारों से अवगत कराया गया। विद्या समीक्षा केंद्र, जादुई पिटारा, सुपर-100, जिज्ञासा, निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इससे पहले, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक सुशील कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त निदेशक डा.दिनेश चंद्र बडोनी ने किया।

संक्षिप्त समाचार...

एक व्यक्ति से 40 हजार रुपये ठग लिए गए

देहरादून संवाददाता. पुरानी कार सस्ते दाम में दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 40 हजार रुपये ठग लिए गए। शिमला बाईपास चौक, निकट सेंट जूड्स स्कूल निवासी कृष्ण कुमार चक्रवर्ती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शामली निवासी मोहन लाल उर्फ सोनू से उनका पिछले चार वर्षों से संपर्क था। मोहन अक्सर उनके लिए दिल्ली-देहरादून व अन्य जगहों के लिए गाड़ी (कैब) की व्यवस्था करता था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उन्हें एक पुरानी ऑल्टो कार दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने कार का सौदा महज 38,000 रुपये में तय किया। कृष्ण कुमार के अनुसार उन्होंने आरोपी के कहने पर बीते 11 दिसंबर को 5,000 रुपये बयाना राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इसके बाद बैंक खाते में 30,000 रुपये और फिर गाड़ी लाने के लिए पेट्रोल व बकाया राशि के नाम पर 5,000 रुपये और भेजे गए। इस तरह पीड़ित ने कुल 40,000 रुपये का भुगतान कर दिया। पैसे मिलने के बाद आरोपी ने 17 दिसंबर को गाड़ी देहरादून पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद 19 दिसंबर के बाद से आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

डिप्लोमा इंजीनियर्स ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

देहरादून संवाददाता. उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर आठ सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियर्स मुखर हो गए हैं। मंगलवार को देहरादून के यमुना कॉलोनी में हुई बैठक में इंजीनियरों ने एकजुट होकर शासन के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया। मंडल अध्यक्ष आशीष यादव ने कहा कि प्रदेश भर के अभियंता अपने सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर हैं। बैठक की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रीकोटी और संचालन जनपद सचिव पूजा श्रेष्ठा ने किया। महासंघ ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2006 से लंबित वेतन विसंगतियों और पदोन्नति के मामलों में शासन का ढुलमुल रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियंताओं ने प्रारंभिक ग्रेड वेतन 4600 करने, 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे रू5400 (लेवल-10) देने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा समयबद्ध पदोन्नति, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और फील्ड कर्मियों के लिए जोखिम भत्ते की मांग भी प्रमुख है। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि अभियंता राज्य की विकास की धुरी हैं, यदि उनकी उपेक्षा हुई तो आंदोलन उग्र होगा। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा, वीरेन्द्र गुसाई, अनिल पंवार, दीवाकर दशमाना, शांतनु शर्मा, मुकेश रतूड़ी, चित्रंजन जोशी, उपेन्द्र गोयल, प्रमोद नेगी और पंकज सैनी आदि मौजूद रहे।

हरिद्वार-रुड़की महायोजना 2041 पर राज्य सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

- राज्य सरकार शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : डॉ. आर. राजेश कुमार

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजनाख़ 2041 के प्रारूप पर आज राज्य सचिवालय, देहरादून में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।भविष्य के शहरों का रोडमैप: बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। शशि मोहन श्रीवास्तव, चीफ टॉउन एंड कन्ट्री प्लॉनर ने इस योजना की बावत सभी महत्वपूर्ण जानकारी सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार से साझा की।

शशि मोहन श्रीवास्तव द्वारा महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए अब तक की गई कार्यवाही और आगामी चरणों की जानकारी दी गई।सार्वजनिक सहभागिता को मिला विशेष महत्व: उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके। नियोजित विकास से सशक्त होगा हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र: आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार एवं रुड़की महायोजनाख़2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके।

हिन्दी दैनिक जोखिम

घोड़े-खच्चरों के पंजीकरण के लिए सीएम का भेजा ज्ञापन

चमोली संवाददाता. वर्ष 2026 की केदारनाथ यात्रा के लिए चमोली जनपद के घोड़ा-खच्चर संचालकों ने यात्रा पंजीकरण करने की मांग उठाई है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सामाजिक कार्यकर्ता भरत सिंह, राकेश सैंजवाल, प्रदीप बर्त्वाल आदि ने ज्ञापन में कहा कि घोड़ा संचालकों ने मुख्यमंत्री से जनपद से 1000 घोड़े-खच्चर सवारियों व 500 खच्चर माल ढुलान के लिए पंजीकृत कराने की मांग की है। कहा, इस वर्ष भी संचालक स्वरोजगार के लिए अपने घोड़े-खच्चरों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से पंजीकरण कराया जा रहा है। कहा, पिछले तीन साल से रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन संचालकों का पंजीकरण नहीं करा रहा है जबकि प्रतिवर्ष संचालक प्रतिवर्ष अपने घोड़े-खच्चरों के साथ गौरीकुंड और सोनप्रयाग पहुंचते हैं। उन्हें इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। घोड़े-खच्चरों की स्वास्थ्य जांच के लिए आयोजित होंगे शिविर: गोपेश्वर। आगामी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पशुपालन विभाग घोड़े-खच्चरों की स्वास्थ्य जांच, पशुधन बीमा, ग्लैंडर्स व इक्वायन इंफ्ल्यूंजा रोग की निगरानी के लिए विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. असीम देव ने बताया कि शिविर 23 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगे। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत करछी, तुगासी व करछों में 23 से 26 फरवरी, थैंग में 27 फरवरी, चांई में एक मार्च, सलूड़-डुंगरा में छह मार्च, उर्गम व कलगोठ में सात मार्च, पल्ला जखोला में नौ मार्च, ईराणी में 23 फरवरी, पगना में 25, निजमुला में 26, सैंजी में 27, पीपलकोटी में एक मार्च, बिरही में 6 मार्च, मैठाणा में सात मार्च, कनोल में 23 फरवरी, पल्टिंगधार में 24, घूनी में 25, सितेल में 26, ल्वाणी में 27, पगना में एक मार्च, भेंटी में 6 मार्च, बांजबगड़ में 7 मार्च, सेरा में नौ मार्च, सेमा में 10 मार्च, कांडई में 11 मार्च व बूरा में 12 मार्च को स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे।

छात्रों को उनके अधिकारों की जानकारी दी

चमोली संवाददाता. अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान के तहत दशोली ब्लॉक के जीआई डुंगरी मैकोट व सावरीसैंण में बाल कल्याण समिति की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र कुनियाल, सदस्य राकेश, अनीता सेमवाल, ममता भट्ट व लक्ष्मी बोरा ने बाल श्रम कानून व बाल अधिकार की जानकारी दी। साथ ही बच्चों की देखभाल, संरक्षण, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, स्पॉन्सरशिप योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, बाल विवाह व मानव तस्करी से सुरक्षित रहने की जानकारी दी।

जल्द नए स्वरूप में नजर आएंगे बाबा बर्फानी, गुफा परिसर में विकसित होगा शिव उद्यान

चमोली संवाददाता. हिमालय क्षेत्र में स्थित बाबा बर्फानी का टिम्मरसैंण गुफा क्षेत्र जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। गुफा तक आवाजाही भी सुगम हो जाएगी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जिला पर्यटन विकास विभाग की ओर से टिम्मरसैंण क्षेत्र को संवारने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग को भारत सरकार से 26 करोड़ 85 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। चमोली जनपद की टिम्मरसैंण गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ शिवलिंग का आकार ले लेता है। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शनों को पहुंचते हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट योजना के तहत गुफा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण व आवाजाही की समुचित सुविधा दिए जाने के लिए पर्यटन विभाग ने भारत सरकार को 2024 में प्रस्ताव भेजा था। इस वर्ष जनवरी माह में इसे स्वीकृति मिली और पर्यटन विभाग को 26 करोड़ 85 लाख रुपये मंजूर हुए। अत्यधिक बर्फबारी न होने के चलते पर्यटन विभाग ने यहां अवस्थापना विकास के काम शुरू कर दिए हैं। गुफा परिसर का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही प्राकृतिक रास्ते का सुधारीकरण किया जा रहा है। रास्ते पर बर्फ के चलते फिसलन रहती है, इसे देखते हुए रेलिंग लगाई जा रही है। रास्ते पर नक्काशीदार पत्थर लगाए जा रहे हैं।

देहरादून राज्य आमंत्रण फुटबाल प्रतियोगिता में विजयी

चमोली संवाददाता. जूनियर बालक वर्ग की तीन दिवसीय राज्य आमंत्रण फुटबाल प्रतियोगिता का खिताब देहरादून की टीम ने कब्जा लिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन देहरादून ने टिहरी को 3-0 अंकों से पराजित किया। नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत और जिला खेल अधिकारी पौड़ी जयवीर सिंह रावत ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। मंगलवार को पहले सेमीफाइनल मुकाबले आयोजित हुए। प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला देहरादून और कोटद्वार के बीच खेला गया। देहरादून ने 3-0 से मैच जीत लिया। टीम के खिलाड़ी हिमांशु ने एक व कार्तिक ने दो गोल दागे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टिहरी और चंपावत के बीच खेला गया। इसमें टिहरी की टीम ने 6-4 अंकों से मैच कब्जा लिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के एक-एक गोल होने से पैनाल्टी शूट के माध्यम से टिहरी की ओर से अभिषेक, अक्षित, धनंजय, सूजल और एक अन्य खिलाड़ी ने एक-एक गोल मारे। चंपावत की ओर से आशीष, आयुष, यश और नैतिक ने एक-एक गोल किए। इसके बाद देहरादून और टिहरी की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें देहरादून ने कड़े मुकाबले में 3-0 अंकों के साथ मैच कब्जा लिया। देहरादून की ओर से कार्तिक ने 48वें व 60वें मिनट में दो गोल मारे। अनुज ने 61वें मिनट में एक गोल मारकर टीम को जीत दिला दी।

शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

चमोली संवाददाता. जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज रडुवा चांदनीखाल में जन-जन की सरकार-जन-जन के द्वार अभियान के तहत बहउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सरकारी विभागों की ओर से शिविर में स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनता से सीधा संवाद किया। उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

अवकाश का वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी

चमोली संवाददाता. माध्यमिक विद्यालयों में तैनात अतिथि शिक्षकों ने शीतकाल व ग्रीष्मकाल अवकाश का वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। मंगलवार को अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रभारी खंड शिक्षाधिकारी से वार्ता कर अवकाश के वेतन का भुगतान नहीं होने पर बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी न करने की बात कही है। मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने बैठक कर प्रभारी बीईओ योगेंद्र सेमवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अतिथि शिक्षकों को जनवरी 2025, जून 2025 व जनवरी 2026 के अवकाश में बच्चों का पढ़ाए जाने का वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों ने शीघ्र समाधान नहीं होने पर विद्यालय संबंधी कार्य व बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार की चेतावनी दी। बीईओ योगेंद्र सेमवाल ने बताया कि गेस्ट टीचरों को शैक्षणिक कार्य का ही भुगतान होना है। शीतकाल व ग्रीष्मकाल अवकाश में काम करने पर ही वेतन मिलेगा। इस बारे में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से रिपोर्ट मांगी जाएगी। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप कुमार, केसी बिष्ट, बीना बिष्ट, रेखा नेगी, बलवंत सिंह, विनोद कुमार, प्रताप सिंह, जयबीर कुमार, दिनेश चंद्र, सुनील कुमार, दीपा रानी, सुरेंद रावत, भावना आदि शामिल थे।

आज औली पहुंचेंगे खिलाड़ी, अभ्यास के लिए नया स्लोप किया तैयार

चमोली संवाददाता. औली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कीइंग चौंपियनशिप के लिए आयोजन समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज सभी राज्यों की टीमें औली पहुंच जाएंगी। आगामी 12 फरवरी से स्कीइंग की प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। आयोजकों ने मंगलवार को चौंपियनशिप के लिए तैयार किए गए दोनों स्लोप का स्थलीय निरीक्षण किया। चौंपियनशिप तक स्लोप पर पर्याप्त बर्फ जमीं रहे, इसके लिए यहां पर्यटकों और आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। बाहर से आने वाले स्कीयरों के लिए एक अन्य स्लोप अभ्यास के लिए तैयार किया गया है। औली में 12 से 16 फरवरी तक विंटर कॉर्निवाल के साथ ही राष्ट्रीय स्कीइंग चौंपियनशिप का आयोजन प्रस्तावित है। विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव राकेशा रंजन भिलंगवाल ने बताया कि स्कीइंग चौंपियनशिप की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था गढ़वाल मंगल विकास निगम (जीएमवीएन) में की गई है। निजी होटलों में भी खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। औली में चौंपियनशिप के लिए तैयार किए गए दोनों स्लोप को नेट फिटिंग कर तैयार कर लिया गया है। कहा कि खिलाड़ियों के लिए दस नंबर टावर के समीप अभ्यास के लिए एक स्लोप तैयार किया गया है।

एमएस रावत बनाए गए पड़ाव समिति के संयोजक

चमोली संवाददाता. श्रीनंदा देवी राजजात के संबंध में नौटी में ग्रामीणों व पड़ाव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में तैयारियों के लिए एमएस रावत को पड़ाव समिति का संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाली छंतोलियों के साथ चलने वाले लोगों का आईडी कार्ड बनाने और सभी पड़ावों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई। मंगलवार को लोनिवि विश्राम गृह में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने राजजात से पूर्व मार्गों की मरम्मत, देवडोलियां और छंतोलियों को ले जाने वाले ग्रामीण एक ड्रेस में होने, छंतोलियों के साथ अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक आदि पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के महासचिव भुवन नौटियाल, कुलदीप सिंह नेगी, संदीप नेगी, पूनम देवी, सतीश टम्टा, मनोज नैनवाल, उपेंद्र प्रसाद, विक्रम सिंह, पवन रावत, हेमा देवी, कर्ण सिंह कोहली, पृथ्वी सिंह आदि मौजूद थे।

कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है एआई, दुरुपयोग से बचना जरूरी

चमोली संवाददाता. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से मंगलवार को सेफर इंटरनेट डे के मौके पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग व डिजिटल जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने कहा, एआई का सही उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है लेकिन इसके दुरुपयोग से बचना अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला में अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुशीला न फिशिंग वेबसाइट्स, ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड,ऑनलाइन स्कैम, एआई के दुरुपयोग व डीपफेक जैसी चुनौतियों की जानकारी दी। अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विशेष चंद्र ने सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही बलइमतबतपउम.हवअ.पद पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने एवं 1930 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर जयवीर सिंह, विमल सिंह, प्रीति सती, अजय बिष्ट, विनय जोशी, शिवराज सिंह आदि मौजूद रहे।

स्थानांतरण व पदोन्नति के लिए दिया धरना

चमोली संवाददाता. स्थानांतरण और पदोन्नति सहित अन्य मांगों के लिए लोनिवि मिनिस्ट्रीयल कर्मियों का कार्यबहिष्कार दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लोनिवि निर्माण खंड थराली के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने विभागीय कार्यालय पर धरना दिया। कहा कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर 13 फरवरी को देहरादून में विभागाध्यक्ष कार्यालय का घेराव व 18 फरवरी को सचिवालय कूच में भी थराली के कर्मी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ कर्मचारी नेता देवराज सिंह राणा, रोशन लाल निराला, मोहन सिंह जलाल, कैलाश चन्द्र, राजेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह आदि ने विचार व्यक्त करते हुए धरना दिया।

ज्योतिर्मठ को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग

चमोली संवाददाता. ज्योतिर्मठ विकास खंड को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए पैनखंडा विकास संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। बताया इस संबंध में न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। सोमवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष भरत सिंह कुंवर ने कहा कि ज्योतिर्मठ विकास खंड को केंद्रीय सूची में शामिल न करने पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने परशुराम चौक ट्रांजिट कैम्प से गांधी पार्क तक बाइक तक रैली निकाली

रुद्रपुर,संवाददाता. 4 श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के विरोध में 12 फरवरी की राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने आज परशुराम चौक ट्रांजिट कैम्प से गांधी पार्क तक बाइक तक रैली निकाली।परशुराम चौक पर हुई संक्षिप्त सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि 12 फरवरी 4 श्रम संहिताओं(कोड्स) को लागू करने से रोकने की मांग पर देशव्यापी हड़ताल आहूत है। जिसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। श्रमिक वर्ग मजदूरों पर हो रहे शोषण से परेशान है। ऊपर से केंद्र सरकार ने मजदूर को बंधुवा गुलाम बनाने के लिए पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर पूंजीपतियों के पक्ष में 4 श्रम कोड्स लागू कर दिए हैं।सभा को संबोधित करते हुए सीएसटीयू के मुकुल ने कहा किसरकार चार श्रम संहिताओं को मीठे मीठे शब्दों में परिभाषित करके मजदूरों को गुमराह कर रही है। ये श्रम कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। पुराने 29 श्रम कानूनों में जो अधिकार मजदूरों को हासिल थे, उन अधिकारों में कटौती करके सरकार ने नए सिरे से 4 श्रम संहिता बना दी हैं। पहले से ही सरकार के मजदूर विरोधी रुख के कारण मजदूर बदहाली में जी रहा था। लेकिन अब नए श्रम संहिताओं में मजदूरों के हालत बंधुआ गुलाम जैसे हो जाएंगे। पहले श्रमिक अपनी योग्यता के दम पर 58 वर्ष की उम्र तक स्थाई नौकरी फैक्ट्रियों में पा लेते थे। लेकिन इन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद स्थाई नौकरी के बजाय निश्चित अवधि यानि फिक्स्ड टर्म जॉब होगी। यह निश्चित अवधि अलग ख़अलग फैक्ट्रियों के स्टैंडिंग ऑर्डर के अलगख़अलग हो सकती है। निश्चित अवधि की नौकरी के बावजूद श्रमिक के ऊपर हमेशा हायर एंड फायर पॉलिसी के तहत फायर होने(नौकरी से निकाले जाने) का खतरा बना रहेगा।इन नए कानूनों के तहत मजदूरों का यूनियन बनाकर अपने हक अधिकार के लिए एकताबद्ध होना और लड़ना असंभव हो जाएगा। जिस कारण कंपनी मालिक मजदूरों का बेतहाशा शोषण करने में कामयाब होगा। नए श्रम संहिताओं में अब कोई भी 300 श्रमिक नियुक्त करने वाला कंपनी मालिक मनमर्जी से जब चाहे तब , बिना राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किए कंपनी बंद कर सकता है। पहले श्रम कानूनों में यह सीमा 100 श्रमिक की थी।देश के श्रम बल को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। देश की जमीनों को ध ड़ल्ले से अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों लूटा रही है। और यह सब देश में अमृतकाल के दौर के नए कानूनों के माध्यम से कर रही है। यानी हर गैर संविध ानिक कार्यवाहियों को संवैधानिक बनाकर पूंजीपतियों का हित साध रही है। इस दौरान भाकपा(माले) के ललित मटियाली, इंकलाबी मजदूर केंद्र के दिनेश चंद्र, ऐक्टू जिला सचिव अनिता अन्ना, हरेंद्र सिंह, महेंद्र राणा, जगमोहन, पुष्कर खाती, भीम सिंह, कमल, डूंगर सिंह, ध ीरज जोशी, हीरा राठौर समेत दर्जनों श्रमिक उपस्थित थे।

योजनाओं की समीक्षा की

भीमताल संवाददाता. /विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पांडे की अध्यक्षता में बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, नंदा गौरा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेन्टर एवं विभागान्तर्गत संचालित अन्य समस्त योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर बैठक आहूत की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि लाभार्थीपरक योजनाओं का पात्र लाभार्थियों को ससमय लाभ दिलाना सुनिश्चित करें तथा कोई पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रहें। जनपद के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं में मॉडल आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना की जाए। कुपोषण से मुक्ति एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु नवाचार गतिविधि यां आयोजित की जाए एव समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नियमित निर्धारित निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान

हल्द्वानी /कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया।पुरानी फर्म के आधार पर विभिन्न कंपनियों को पंजीकृत कर उसके आधार पर भू काननू का उल्लंघन कर फर्जी

तरीके से भूमि क्रय करते हुए भूमि दस्तावेजों के आधार पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामले पर आयुक्त ने इस प्रकरण पर जांच करते हुए खिलाफ कठोर शिकायत काशीपुर से आई, जिसमें लोगों द्वारा पुरानी फर्म के आधार पर 5 नई कम्पनियां बनाकर एवं भू-कानून का उल्लंघन कर विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय करने व भूमि के दस्तावेजों के आधार पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत को आयुक्त ने गम्भीरता से लेते हुए उपजिलाधि कारी को शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा इस प्रकार का कृत्य कतई स्वीकार नही किया जायेगा जो भी इसमें संलिप्त होगा उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जनसुनवाई में लोगों द्वारा शिकायत की गई कि हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डा के बाहर निजी एवं रोडवेज की बसें खडी कर सवारियों को गन्तव्य स्थानों के बिठाया जाता है ।

' सरकार कर रही है आशाओं का शोषण, चाहिए नियमित वेतन, पक्की नौकरी और सम्मान : ममता पानू

रुद्रपुर संवाददाता.' मजदूर अधिकारों पर आजादी के बाद का सबसे बड़ा हमला,4 श्रम संहिताओं को वापिस लेने की मांग को लेकर 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होगी उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) रुद्रपुर गल्ला मंडी में प्रदर्शन करेंगी : अनीता अन्नाट्रेड यूनियन ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की गदरपुर ब्लॉक कमेटी ने मीटिंग करके 12 फरवरी की हड़ताल में जाने का चिकित्साधिकारी को दिया नोटिस।उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) की जिला उपसचिव अनीता अन्ना ने कहा कि, मोदी सरकार मजदूरों, महिला कामगारों के अधिकारों पर हमला कर रही है,आशा वर्कर्स की हालत सभी उत्पीड़ित श्रमिकों में सबसे ज्यादा खराब है. उन्हें तो श्रमिक का दर्जा भी नही दिया जाता, बंधुवा मजदूर की तरह काम लिया जाता है. आशा वर्कर्स पर सरकार नए नए काम का बोझ लगातार बढ़ाते जा रही है. शिशु मृत्यु दर कम करने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, गर्भवती महिलाओं की देख-रेख के लिए आशाओं को आधी रात में भी बिना किसी विभागीय सहायता के दौड़ना पड़ता है. इसके बावजूद आशा वर्कर्स को वेतन देने के नाम पर सिर्फ नाममात्र की प्रोत्साहन राशि और कुछ योजनाओं का कमीशन दिया जाता है. यह खुला शोषण कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होंगी ।

अल्मोड़ा में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने की मेडिकल स्टोरों की जांच

अल्मोड़ा संवाददाता. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा गठित क्विक रिस्पांस टीम ने जनपद अल्मोड़ा में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। टीम में औषधि निरीक्षक अल्मोड़ा पूजा जोशी और औषधि निरीक्षक बागेश्वर पूजा रानी शामिल रहीं। अभियान के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप, मन:प्रभावी औषधियों की बिक्री, एंटीबायोटिक दवाओं की चिकित्सकीय पर्चे पर बिक्री तथा सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता और रिकॉर्डिंग का गहन सत्यापन किया गया। अभियान के तहत लोअर मॉल रोड और बेस अस्पताल क्षेत्र में स्थित विभिन्न मेडिकल रिटेल और होलसेल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि औषधियों का क्रय-विक्रय वैध लाइसेंस के तहत और पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की गई कि कोडीन युक्त कफ सिरप, मन:प्रभावी औषधियां और एंटीबायोटिक दवाएं केवल विधिवत चिकित्सकीय पर्चे पर ही दी जा रही हैं। टीम ने मेडिकल स्टोरों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उनकी रिकॉर्डिंग व्यवस्था की भी गहन जांच की। औषधि निरीक्षक पूजा जोशी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशीली और मन:प्रभावी दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना और आम जनता, विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रखना है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आगामी चुनावों की तैयारी तेज आजाद समाज पार्टी ने रामनगर में संगठन मजबूत किया

रामनगर संवाददाता. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने रामनगर क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में पार्टी के कुमाऊं मंडल प्रभारी लेखराज गौतम ने रामनगर निवासी शाहरुख शेरिया को रामनगर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि यह नियुक्ति संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से की गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पार्टी लगातार विस्तार पर जोर दे रही है।शाहरुख शेरिया के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा संगठन को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई।

हिन्दी दैनिक जोखिम

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जनक एफ.डब्लयू. चौम्पियन को किया याद

रामनगर संवाददाता. पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में उत्तराखंड के एक गर्वित हरित नायक भारतीय वन्यजीव फोटोग्राफी के जनक एफ.डब्लयू. चौम्पियन की स्मृति में विशेष सत्र का आयोजन किया गया।इस अवसर पर उनके पोते जेम्स चौम्पियन द्वारा एक इंटरैक्टिव सत्र में एफ. डब्ल्यू. चौम्पियन के जीवन, कार्य और उनके फोटोग्राफिक योगदान पर प्रकाश डाला गया।भारतीय वन्यजीव फोटोग्राफी के जनक एफ. डब्ल्यू. चौम्पियन भारत के प्रारंभिक वन अधिकारियों में से एक थे।जो यह मानते थे कि वन्यजीवों को शिकार के माध्यम से नहीं, बल्कि अवलोकन और फोटोग्राफी के जरिये समझा और संरक्षित किया जाना चाहिए। 1920ख30 के दशक में उन्होंने भारत में नैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी की शुरुआत की और प्रारंभिक कैमरा-ट्रैप तकनीकों का उपयोग किया, वह भी बिना किसी प्रकार की बाधा पहुँचाए।उनकी सोच अपने समय से कहीं आगे थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि फोटोग्राफी केवल दस्तावेजीकरण का माध्यम नहीं, बल्कि जागरूकता और संरक्षण का एक सशक्त साधन हो सकती है। उन्होंने जिम कॉर्बेट को भी बंदूक छोड़कर कैमरा और लेखन अपनाने के लिए प्रेरित किया जिसने आगे चलकर भारत के संरक्षण इतिहास की दिशा बदल दी।इन महत्वपूर्ण योगदानों के कारण एफ. डब्ल्यू. चौम्पियन को सम्मानपूर्वक "भारतीय वन्यजीव फोटोग्राफी का जनक" कहा जाता है। प्राचार्य प्रो.एम.सी.पाण्डे ने मुख्य अतिथि जेम्स चौम्पियन सहित अन्य लोगों का स्वागत किया।मंच का संचालन डॉक्टर डीएन जोशी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रो.जी.सी.पन्त,डॉ.प्रियदर्शन बेलवाल, पूर्व मंत्री धनेश्वरी घिल्डियाल, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गणेश रावत,सुमन्ता घोष, पर्यावरण प्रेमी इमरान खान,संजय छिम्वाल, हरिशंकर,सुरेश सिंह,ख्याली दत्त करगेती, गौरव करगेती, उमाशंकर बिष्ट,मोहन सिंह, नन्दन सिंह नेगी,रवि देशवाल, प्रियंका आदि मौजूद रहें।

एक चलती टाटा पंच कार में अचानक आग लग गई

हल्द्वानी संवाददाता.के लामाचौड़ क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती टाटा पंच कार में अचानक आग लग गई। कार सवार चालक ने समय रहते वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।जानकारी के अनुसार, गांधी आश्रम पीपलपोखरा नंबर-1 निवासी करण

नेगी अपनी टाटा पंच कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान चलते वाहन से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार में आग भड़क उठी। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तत्काल कार को सड़क किनारे खड़ा किया और बाहर निकलकर सुरक्षित दूरी बना ली।घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी मिंदर पाल सिंह ने बताया कि आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, हालांकि वाहन पूरी तरह से जल गया है।दमकल टीम में भुवन चंद्र जोशी, अनुज शर्मा, श्याम सिंह नैनवाल, प्रेम प्रकाश राणा, देवेंद्र कुमार सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

5000 शुल्क का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया

रामनगर संवाददाता. नगर पालिका परिषद रामनगर के क्षेत्र में शामिल हुए कानिया पंचायत घर और रामलीला मैदान में वैवाहिक समारोह करने के नाम पर नगर पालिका द्वारा लिए जा रहे 5000 शुल्क का स्थानीय निवासियों ने

विरोध किया।शुल्क कम करने को लेकर लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम का घेराव करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।दिए गए ज्ञापन में लोगो ने कहा कि कानिया और उसके आसपास के लोग अपने वैवाहिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए इसी मैदान पर करते हैं।पूर्व में ग्राम सभा होने पर यहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, जो शुल्क अगर होता भी था तो वह नाममात्र का था, लेकिन नगर पालिका द्वारा5000 शुल्क लिया जा रहा है जो कि अनुचित है। उन्होंने जल्द से जल्द इस शुल्क को वापस लेने की मांग की है।नगर पालिकाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने कहा कि शुल्क राशि कम ली जाएंगी।जिस पर यह सहमति बनी की पालिका 2500 शुल्क लेगी जिसमें बिजली पानी साफ सफाई भी सम्मिलित होगी इस दौरान आनंद रावत, प्रमोद उप्रेती,राजू,सत्येंद्र चौहान, सारिका जोशी,कपिल रावत,गणेश दत्त जोशी आदि लोग मौजूद रहें।

लोग धोखागाडी और जालसाजी की शिकायत लेकर पहुंचे

हल्द्वानी संवाददाता. स्थित एस.एस.पी.मंजूनाथ टी.सी.के कार्यालय में आज दोपहर दर्जनभर लोग धोखागाडी और जालसाजी की शिकायत लेकर पहुंचे। सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायत थी कि हल्दूचौड़ के एक सुनार ने उनके साथ सोने के आभूषण बनाने के नाम पर धोखा की है। सुनार नरेंद्र(नीरज)ने कई लोगों से रुपये व सोना चांदी लिया, लेकिन तय समय से देने की जगह वह पहले ही रफूचक्कर हो गया।हल्द्वानी के गुजरौड़ा निवासी पुष्पा कन्याल ने एस.एस.पी.को शिकायत देकर कहा कि उन्होंने नीरज को एक लाख और पिचासी हजार(1. 85लाख)रुपये देकर 20ग्राम सोने का आभूषण बनाने को दिया था। उन्हें, बीती 8 फरवरी को उनका आभूषण मिलने की बात कही गई थी, लेकिन इससे पहले ही 6 फरवरी को नीरज दुकान बंद कर फरार हो गया। तभी से नीरज का मोबाइल नंबर भी बन्द आ रहा है। घर पर उनकी पत्नी सामान वापस करने से इनकार कर रही है। कहा कि इसकी शिकायत सोमवार को मुखानी थाने में भी दी गई थी।आरोप लगाए गए कि नीरज 6 फरवरी से लोगों का सोना लेकर भागा है। उसने 20ग्राम, 21 ग्राम, 26 ग्राम व अन्य से सोने के आभूषण चमकने व बनाने के नाम पर रुपये लिए और फरार हो गया।एस एस पी ने सामूहिक धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और मुखानी थाना एस ओ सुशील जोशी को जांच सौपी है।

कोसी बैराज पर सुर्खाबों की संध्या उड़ान बनी आकर्षण, सूरज ढलते ही उमड़ती है पक्षी प्रेमियों की भीड़

रामनगर संवाददाता. मध्य एशिया से लंबी यात्रा कर भारत आने वाले रूडी शेल्डक, जिन्हें स्थानीय भाषा में सुर्खाब कहा जाता है, इन दिनों कोसी नदी और कोसी बैराज क्षेत्र में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खासकर कोसी बैराज और कोसी कैफे के आसपास है, जब बड़ी संख्या में स्थानीय लोग की एक झलक पाने के लिए एकत्रित कारण सुर्खाब पक्षियों की सामूहिक संध्या ये सुर्खाब पक्षी कोसी बैराज क्षेत्र से एक के लिए अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर चले साथ उड़ते इन पक्षियों का दृश्य बेहद फड़फड़ाहट और सामूहिक आवाज पूरे कारण है कि हर शाम सूरज ढलने से पहले

के आसपास पहुंचकर इस खास पल का इंतजार करते हैं। कई लोग मोबाइल और कैमरों में इस दुर्लभ दृश्य को कैद करते नजर आते हैं, ताकि इन खूबसूरत यादों को हमेशा अपने पास संजो कर रख सकें।स्थानीय लोगों का कहना है कि सुर्खाब पक्षियों की यह संध्या उड़ान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए सुकून देने वाला अनुभव है, बल्कि यह क्षेत्र के लिए एक प्राकृतिक पर्यटन आकर्षण भी बनती जा रही है। यदि इस तरह के प्राकृतिक नजारों को संरक्षित और प्रचारित किया जाए, तो आने वाले समय में कोसी बैराज क्षेत्र पक्षी पर्यटन के लिहाज से एक खास पहचान बना सकता है।

शाम होते ही नजारा देखते ही बनता और पक्षी प्रेमी इन प्रवासी पक्षियों हो जाते हैं।दरअसल, इसका मुख्य उड़ान है।जैसे ही सूरज ढलने लगता है, साथ उड़ान भरते हैं और रात्रि विश्राम जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में एक मनमोहक होता है। उनके पंखों की वातावरण को जीवंत कर देती है।यही ही लोग कोसी बैराज और कोसी कैफे

एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा

रामनगर संवाददाता. करणी सेना ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंजरपड़ाव रामनगर में बच्चों के लिए भवन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है।भेजे गए ज्ञापन में करणी सेना ने कहा कि रामनगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंजरपडाव में खुले

टीनशैड के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, यहां मंदिर समिति के लिए विधायक निधि से दो कमरे बने हैं, लेकिन बच्चों के क्लासरूम बनाने के लिए शिक्षा विभाग या अन्य किसी के पास बजट नहीं है, यहां बच्चे बहुत होनहार है, लेकिन सिस्टम की उदासीनता बच्चों की मेहनत पर भारी है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस और ध्यान देकर स्कूली बच्चों के लिए भवन उपलब्ध कराने की मांग की है।इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी,प्रदेश संगठन महामंत्री हरीश प्रकाश,प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर शर्मा,जिला अध्यक्ष युवा शक्ति सुभाष,जिला उपाध्यक्ष युवा शक्ति लखन,विधानसभा अध्यक्ष शंकर आदि मौजूद रहें।

हिन्दी दैनिक जोखिम

अस्सी का ट्रेलर आउट, दमदार अंदाज में दिखीं तापसी पन्नू

निर्देशक अनुभव सिन्हा और अभिनेत्री तापसी पन्नू की जोड़ी एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आई है। श्मुल्कश और श्थप्पड़श जैसी सफल फिल्मों के बाद अब ये जोड़ी फिल्म श्अस्सीश लेकर आई है। पिछले दिनों फिल्म की घोषणा की गई थी, तबसे ही दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। अब आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर काफी दमदार लग रहा है और एक बार फिर अनुभव सिन्हा अपनी फिल्म के जरिए कई सवाल खड़े करते हैं।2 मिनट 52 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत कोर्ट में वकील के तौर पर तापसी पन्नू के किरदार से होती है। जहां वो बताती हैं कि श्अपराध वाले दिन देशभर में 80 रेप कंपलेंट हुई थीं, जिनमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ हैश इसके बाद दिखाया जाता है कि एक महिला को एक कार से किडनैप कर लिया जाता है। बाद में उस महिला का गैंगरेप करके उसको रेलवे पटरियों के पास छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस चलता है। श्अस्सीश एक कोर्टरूम ड्रामा जिसमें बलात्कार जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात की गई है। फिल्म में तापसी पन्नू एक वकील के किरदार में नजर आई हैं, जबकि कानी कुसृति ने रेप पीड़िता की भूमिका निभाई है। ट्रेलर से पता चलता है कि अनुभव सिन्हा एक बार फिर एक दमदार कहानी लेकर आए हैं, जो बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाती है।अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म की स्टारकास्ट काफी दमदार है। फिल्म में तापसी पन्नू के अलावा मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, कानी कुसृति और रेवती भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

ट्रेलर में इन सभी किरदारों की भी झलक देखने को मिलती है। श्अस्सीश 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर देखकर कई बार आपको श्पिंकश और श्आर्टिकल 15श जैसी फिल्मों की झलक भी दिखेगी।अनुभव सिन्हा की फिल्मों का वैसे भी दर्शकों को काफी इंतजार रहता है। तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की ये साथ में तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों साथ में मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्में कर चुके हैं। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हुई थीं और क्रिटिकली भी फिल्म को काफी पसंद किया गया था। ऐसे में अब ये जोड़ी अस्सी लेकर आ रही है। इसलिए दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।

अर्जुन सरजा की फिल्म सीता पयनम की रिलीज डेट से उठा पर्दा, 14 फरवरी पर वर्ल्डवाइड होगी रिलीज

सिनेमा में जब कोई फिल्म परिवार, प्यार और एक्शन को साथ लेकर आती है, तो उसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। इस कड़ी में अभिनेता और निर्देशक अर्जुन सरजा की नई फिल्म सीता पयनम को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। यह फिल्म रोमांचक कहानी से भरपूर है।दर्शक फिल्म से जुड़ी हर एक छोटी-छोटी अपडेट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब फिल्म निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। सीता पयनम का निर्माण श्रीराम फिल्म्स कर रही है, और यह अर्जुन सरजा का नया निर्देशन प्रोजेक्ट है।फिल्म में एक्शन, ड्रामा और पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण है, यह सभी उम्र के दर्शकों का मनोरंजन करेगा। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करते हुए श्रीराम फिल्म्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, प्यार से, शुक्रगुजारी से, एक सफर शुरू होता है।सीता पायनम यह फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 14 फरवरी 2026 पर वर्ल्डवाइड रिलीज होगी। यह दुनिया भर में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। फिल्म में अर्जुन सरजा की बेटी, ऐश्वर्या अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं।फिल्म की कहानी उनके किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके अलावा, फिल्म में निरंजन, सत्यराज, प्रकाश राज और कोवई सरला जैसे अनुभवी कलाकार भी हैं। फिल्म में अर्जुन सरजा खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं उनके भतीजे ध्रुवा सरजा ने भी फिल्म में एक विशेष भूमिका निभाई है।फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत है। सिनेमेटोग्राफी जी. बालामुरुगन संभाल रहे हैं, जबकि अनूप रूबेंस फिल्म में दमदार म्यूजिक देंगे। एडिटिंग का काम अयूब खान कर रहे हैं और साई माधव बुरा ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। एक्शन और स्टंट सीक्वेंस बाबू ने डिजाइन किए हैं।

विश्वक सेन की फिल्म फंकी का ट्रेलर रिलीज, 13 फरवरी को होगी ग्रैंड रिलीज

मास का दास विश्वक सेन अपनी आने वाली फिल्म फंकी के साथ फिल्म प्रेमियों का मनोरंजन करने आ रहे हैं, जिसका टाइटल काफी दिलचस्प है।जाति रत्नालु फेम केवी. अनुदीप द्वारा निर्देशित यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म वैलेंटाइन्स डे स्पेशल के तौर पर रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोशन, गाने और टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आज मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज किया।ट्रेलर में बहुत सारे मजेदार एलिमेंट्स हैं। के.वी. अनुदीप की डायरेक्शन और विश्वक सेन के अंदाज ने सभी का ध्यान खींचा। विश्वक सेन के एक्सप्रेशंस और मजेदार डायलॉग्स और कायाडू लोहार की मौजूदगी ने फिल्म में ग्लैमर जोड़ा। नरेश और वीटीवी गणेश ने फिल्म में विश्वक सेन के साथ मिलकर कॉमिक टच दिया।फिल्म का म्यूजिक भीम्स सेसिरोलियो ने दिया है, जबकि नागा वामसी एस और साई सौजन्या सितारा एंटरटेनमेंट्स, फॉर्च्यून फोर सिनेमाज और श्रीकरा स्टूडियोज के बैनर तले फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं।रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 8 मिनट तय किया है।

पिंक लहंगे में पलक तिवारी मचाया गदर, ग्लैम लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

एंटरटेनमेंट की दुनिया में श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर अकसर सुर्खियों में छाई रहती हैं, लेकिन इश बार उनकी बेटी यंग डीवा पलक तिवारी ने अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स से अपनी मां को भी पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में पलक ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं. आइए जानते हैं इस हसीना का लेटेस्ट लुक क्यों बना चर्चा का विषय.बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह पिंक कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. जिसपर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.मिरर वर्क वाले इस खूबसूरत लहंगे ने पलक की खूबसूरती को और भी निखार दिया है. इस लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहना है, जिसने उनके पूरे लुक में एक ग्लैमरस टच जोड़ा है.पलक ने अपने पूरे लुक को सिंपल लेकिन एलिगेंट रखा. उन्होंने सटल मेकअप, मैचिंग इयररिंग्स और खुले बालों के साथ अपने स्टाइल को कंप्लीट किया है. जिसमें वो किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रहीं हैं.उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है और कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि पलक अपने हर नए लुक के साथ खुद को और ज्यादा स्टाइलिश साबित करती हैं.इन तस्वीरों में देखा जा सकता हैं, कि पलक कैसे एक से बढ़कर एक पोज दे रहीं हैं, कभी जमीन पर बैठकर तो कभी खड़े होकर एक्ट्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किलर पोज जे रहीं हैं, जो फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं.इन तस्वीरों में खास बात है, पलक पिंक कलर का आउटफिट और वहीं पलक का पिंक मेकअप जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही हैं, इशकी के साथ पलक ने इन फोटोज के लिए पिंक कलर के बैकग्राउड को भी चुना है.पलक तिवारी की हाल ही में द भूतनी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ संजय दत्त, मौनी रॉय जसे सितारे नजर आए थे, फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फैंस को पलक की एक्टिंग खूब पसंद आई.

हिन्दी दैनिक जोखिम

मुख्यमंत्री धामी ने की उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा

- राज्य के दोनों मंडलों में होंगे उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन के निर्माण

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित भवनों में बैंकट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र

लाभार्थियों को योजनाओं जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय नेगी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लक्सर मेडिकल एसोसिएशन का गठन, ओमपाल भाटी बने अध्यक्ष

रुड़की संवाददाता. पिछले कई दिनों से लक्सर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर चली आ रही खींचतान पर आखिर विराम लग गया। एसोसिएशन की बैठक में ओमपाल सिंह भाटी को सर्वसम्मति से लक्सर मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष और अमित कुमार को महामंत्री चुन लिया गया है। इसके साथ कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई है। लक्सर कस्बे में 50 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं। इसके अध्यक्ष अब तक डॉ. प्रेम सिंह पुंडीर को बनाया गयगा था। पिछले दिनों डॉ. प्रेम सिंह पुंडीर का विरोध कर कुछ लोगों ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी थी। बाद में उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया था। सोमवार रात लक्सर कस्बे में लक्सर मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से ओमपाल सिंह भाटी को अध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल को बनाया गया है। महामंत्री पद पर अमित कुमार, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, मंत्री प्रवीण कुमार शर्मा और सलाहकार सचिन पवार को नियुक्त किया गया है। बैठक में राजकुमार गुप्ता, अनुज कुमार, हरेंद्र अग्रवाल, अमजद अली, मनोज शर्मा, रमेश चंद शामिल किए गए। संरक्षक की जिम्मेदारी डॉ. प्रेम सिंह पुंडीर को दी गई है।

संक्षिप्त समाचार...

चूना भट्टा में जान-पहचान वालों ने युवक पर किया हमला

देहरादून संवाददाता. रायपुर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा, रेन बसेरा के पास पुरानी जान-पहचान में एक युवक पर हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई सोनू निवासी रायपुर ने तहरीर में कहा कि उसका भाई राहुल आठ फरवरी की रात करीब 10:30 बजे चूना भट्टा गया था। वहां उसे कुलवंत कुमार (ड्राइवर) और राजेश कुमार (हलवाई) मिले। आरोप है कि दोनों ने एक राय होकर राहुल पर धारदार हथियार से वार कर दिया। हमले में राहुल के गले पर गंभीर चोट आई है। उसे पहले कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सोनू की शिकायत पर कुलवंत और राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला

देहरादून संवाददाता. रायपुर रोड स्थित डील फैक्ट्री के पास अज्ञात आरोपियों ने घर लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शांति विहार, वाल्मीकि बस्ती निवासी दीपक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई गौरव अपने पड़ोसी अनिल के साथ चूना भट्टा से वापस आ रहा था। आठ फरवरी की रात करीब 9:30 बजे शांति विहार मोड़ के पास अज्ञात लोगों ने गौरव पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। पड़ोसी अनिल ने घटना की सूचना परिजनों को दी। घायल गौरव का इलाज दून अस्पताल में चल रहा है। रायपुर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

गलत दिशा से आ रही कार ने नई गाड़ी को मारी टक्कर

देहरादून संवाददाता. राजपुर रोड स्थित एलोराज बेकरी के सामने गलत दिशा से ओवरटेक कर रही एक दिल्ली नंबर की कार ने एक नई गाड़ी को टक्कर मार दी। काठबंगला निवासी अनीता कन्नौजिया ने धारा चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि आठ फरवरी को ही उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी और वह घंटाघर से घर लौट रही थीं। तभी एलोराज बेकरी के पास दिल्ली नंबर की गाड़ी ने गलत साइड से आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक हरीश गुप्ता निवासी पैसिफिक गोल्फ एस्टेट के खिलाफ केस दर्ज किया है।

घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने के मामले में सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुड़की संवाददाता. थाना क्षेत्र के ग्राम लालवाला में आपसी विवाद के बाद घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के सात नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्राम लालवाला निवासी अश्वनी कुमार ने थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। जाते समय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

एन.आई.सी. द्वारा "सेफर इंटरनेट डे-2026" का आयोजन

देहरादून संवाददाता. एनआईसी उत्तराखंड द्वारा विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के सहयोग से दिनांक 10 फरवरी 2026 को देहरादून में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में "सेफर इंटरनेट डे" का आयोजन किया गया। इस विषय पर राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य प्रतिभागियों को साइबर क्राइम तथा साइबर जागरूकता के बारे में अवगत कराया गया । इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राय: हो रहे अनलाइन फ्रॉड एवं ए.आई. का दुरुपयोग जैसे डीपफेक एवं अन्य प्रकार के फ्रॉड से समाज को सुरक्षित करने की जागरूकता फैलाना है । इस संबंध में स्वयं तथा परिजनों को जागरूक करने की आवश्यकता है । भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के द्वितीय मंगलवार को "सेफर इंटरनेट डे" का आयोजन किया जाता है । इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ट नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट वातावरण को बढ़ावा देना है। यह एक अंतरराष्ट्रीय जागरूकता अभियान है जो जिम्मेदार और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस "स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प। ए.आई. के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग" थीम पर केंद्रित रहा । इस अवसर पर रा.बा.ई.का. राजपुर रोड तथा रा.ई.का. रायपुर में लगभग 200 तथा वर्चुअल माध्यम से 1100 से अधिक स्कूलों में लगभग 30000 विद्यार्थिओं ने प्रतिभाग किया । इसके अतिरिक्त 200 स्थानों से यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से भी प्रतिभाग किया गया । इन कार्यशालाओं के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए । विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को साइबरबुलिंग, व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता, और ऑनलाइन फ्रॉड (जैसे फिशिंग, बैंकिंग धोखाधड़ी) के बढ़ते खतरों से बचाव के उपयोग बताए। साइबर हाइजीन तथा ए.आई. के जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या अपनी लोकेशन सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने से बचें। अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बलइमतबतपउम.हवअ.पद या टॉल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। इस अवसर पर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उपमहानिदेशक ए. के. दधीचि तथा उनकी टीम के सदस्य राजीव जोशी, हिमांशु कुमार, सुश्री पुष्पांजलि, कैलाश किमोठी, रोहित चंद्रा, शक्ति रतूड़ी, सुश्री कनुप्रिय गाबा, सुश्री रचना एवं सौरभ रतूड़ी उपस्थित रहे ।

स्वामी, प्रकाशक एवम मुद्रक संजीव पंत द्वारा 19.सी, सुभाष रोड, पैसेफिक होटल के पीछे डूंगा हाउस देहरादून से प्रकाशित एवं चिराग पब्लिकेशन्स डी-2, शिवलोक कालोनी लाडपुर, ब्लॉक रायपुर काली मन्दिर के पास, देहरादून से मुद्रित। सम्पादक - संजीव पंत , फोन नं0- 0135-2712118 , प्रसार प्रबंधक: वसीम अहमद , आर एन आई नं.: UTTHIN/2010/33537 email: jokhimdehradun2006@gmail.com